



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

शासकीयता से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

म 763] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1992/अग्रहायन 11, 1914
No. 763] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 1992/AGRAHAYANA 11, 1914

इस भाग में खिल्म पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि गहरा अलग होकर उपर्युक्त पर्याप्त रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed on a separate compilation

उद्घोष मंत्रालय

(आधिकारिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1992

का.आ. 882(ग्र).—केन्द्रीय सरकार, उद्घोष (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) को आगा 29 वाँ की उम्रावारा (29) के अनुपर्यन्त में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), गारांख 6 जून, 1990 में प्रकाशित, भारत सरकार के उद्घोष गंतालय (र्ह आधिकारिक विकास विभाग) का अधिसूचना संख्यांक का का.आ. 459 (ग्र) तारीख 6 जून, 1990 की अधिकाल सहते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को मिलाकर एक सलाहकार समिति गठित करते हैं जो धारांपालिक, वा

लघु उद्योग, औद्योगिक उत्पक्षीय द्वारा उत्पादन के लिए अरक्षित किसी वस्तु या वस्तुओं के बांग की प्रकृति के प्रवधारण के माध्यमे में घपनी विशेषज्ञ मताह देगी, अर्थात्-

शारकण संबंधी सलाहकार समिति

- | | |
|---|-------------|
| 1. सचिव, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण विभाग, उद्योग मंत्रालय, | —भाष्यक |
| 2. सचिव, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास महानिवेणालय | —सदस्य |
| 3. अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और कीमत इयरों | —सदस्य |
| 4. अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग | —सदस्य |
| 5. अपर सचिव, और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) | —भरतीय सचिव |

2. सलाहकार समिति, निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के पश्चात घपनी सिफारिशें केवलीय सरकार को भेजेगी।

- (क) किसी ऐसी वस्तु या ऐसे बांग की वस्तुओं की प्रकृति, जिनका आनुवांशिक या लघु उद्योग, औद्योगिक उत्पक्षीय द्वारा कियायी रूप में उत्पादन किया जा सकता है,
- (ख) नियोजन का ऐसा स्तर जिसके आनुवांशिक या लघु उत्पक्षीय द्वारा ऐसा वस्तु या ऐसे बांग की वस्तुओं के उत्पादन द्वारा जनन होते थे संभवता है;
- (ग) उद्योग में उत्तमता को प्रोत्साहित करने और प्रमारित करने की सम्भालता,
- (घ) सर्वसाधारण के लिए अहिनकारी आधिक प्रक्रिया को संकेन्द्रण का निवारण; और
- (ङ) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें मनाहकार समिति योक समझे।

[फा. रु. 10/14/90/एस. पी]

इ.एन. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1992

S.O. 882(E).—In pursuance of sub-section (2B) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number S.O. 459(E), dated the 6th June, 1990, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 6th June, 1990, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following persons, for giving its expert advise in the matter of determining the nature of any

article or class of articles that may be reserved for production by the ancillary, or small scale, industrial undertakings, namely ---

ADVISORY COMMITTEE ON RESERVATION

1. Secretary, Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries, Ministry of Industry. Chairman.
 2. Secretary, Technical Development, Directorate General of Technical Development Member.
 3. Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices Member.
 4. Additional Secretary, Department of Industrial Development Member.
 5. Additional Secretary and Development Commissioner (Small Scale Industries) Member-Secretary.
2. The Advisory Committee shall, after considering the following matters, communicate its recommendations to the Central Government, namely :—
- (a) the nature of any article or class of articles which may be produced economically by the ancillary, or small scale, industrial undertakings;
 - (b) the level of employment likely to be generated by the production of such article or class of articles by the ancillary, or small scale, industrial undertakings;
 - (c) the possibility of encouraging and diffusing entrepreneurship in industry;
 - (d) the prevention of concentration of economic power to the common detriment; and
 - (e) such other matters as the Advisory Committee may think fit.

[F. No. 10/14/90-LP]
E. N. MURTHY, Jt. Secy

